

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून दिनांक 08 सितम्बर, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत के 0पो0) योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1062/XVII-4/2015-10(43)/2014 दिनांक 23.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत के 0पो0) योजनान्तर्गत अनुदान सं0-30 के आयोजनागत मद में कुल धनराशि ₹73.01 करोड़ आपके निर्वर्तन पर व्यय हेतु रखी गयी है।

3. उक्त धनराशि के भुगतान हेतु यह स्पष्ट करना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-14011/9/2015-SCD.V दिनांक 31.05.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये ₹20.62 करोड़ आवंटित किया गया है। भारत सरकार से दूरभाष पर हुई वार्तानुसार ज्ञात हुआ कि अब वर्ष 2014-15 के लिये कोई भी धनराशि छात्रवृत्ति मद में आवंटित नहीं की जायेगी। स्पष्ट है कि भारत सरकार से अब उक्त मद में कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं होगी।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त उक्त धनराशि को तद्वर्ष की देयता के आधार पर ही शासनादेश सं0-629/XVII-4/2015-01(10)/2015 दिनांक 26.03.2015 में निर्धारित प्रक्रिया यथा- जिन-जिन शिक्षण संस्थाओं की छात्रवृत्ति की जांच जिलाधिकारी द्वारा की जा चुकी है तथा जांच आख्या में कोई आपत्तिजनक तथ्य इंगित नहीं हैं, अध्ययनरत

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल देय धनराशि का 50 प्रतिशत उन छात्रों को जिनके आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुए हैं, को सुनिश्चित करते हुए अवरोही क्रम में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि का ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

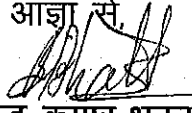
(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)  
सचिव।

संख्या— 1115 (1)/XVII-4/2015-10(43)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

  
(राजेन्द्र कुमार भट्ट)  
उप सचिव।